[Shri Jairam Ramesh]

indexed to CPIAL would be done annually. Thereafter, in July, 2011, it was decided that this revision would become effective on April 1 each year.

2. A notification revising MGNREGA wage rates for the period April 1, 2014 to March 31, 2015 indexed to CPIAL has been issued and is placed on the Table of the House."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be done. Now, further discussion on the Statutory Resolution moved by Shri R.P.N. Singh on the 20th February, 2014. ...*(Interruptions)*...

श्री के.सी. त्यागी : सर, हम चाहते हैं कि मनरेगा पर...**(व्यवधान)**...

DR. K. P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, a copy of the Statement has not been made available. ...*(Interruptions)*...

STATUTORY RESOLUTION

Approving Order issued by President on the 16th February, 2014 in relation to Government of National Capital Territory of Delhi

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Sir, I beg to move:

"That this House approves the Order under Article 239AB of the Constitution issued by the President on the 16th February, 2014 read with Section 50 of the GNCTD Act, 1991 and clauses (2) and (3) of Article 356 of the Constitution in relation to the Government of National Capital Territory of Delhi."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we wanted to pass it quickly. However, we have added one or two names. Shri Dharmendra Pradhan, would you like to say something on the Resolution? We have to approve a Resolution in relation to the NCT of Delhi being under President's Rule. Are you speaking on that?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, what about Delhi's budget?

श्री उपसभापति : बजट इसके बाद लेंगे। यह बजट नहीं है रेज़ोल्यूशन है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : यह सिर्फ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह रेज़ोल्यूशन है।

श्री आर.पी.एन. सिंह : यह बजट नहीं है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान (बिहार) : उपसभापति महोदय, आज जिस सत्ता पक्ष से...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अगर आपने बजट पर बात करनी है तो आपको बाद में अवसर देंगे।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, हम दोनों पर ही बात कर लेंगे।

श्री आर.पी.एन. सिंह : बजट का बिल तो अभी हमने पेश ही नहीं किया है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : नहीं, यह जो राष्ट्रपति शासन आपके कारण आया है, उस पर भी हम दो शब्द बोल देते हैं।

उपसभापति महोदय...(**व्यवधान**)... अरे, पंडित जी, आप सुन तो लीजिए, यह आप ही का कारनामा है।

उपसभापति महोदय, यह एक विचित्र स्थिति है...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्रधान जी,...(**व्यवधान**)...

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I am submitting it. I would be saying just a few lines on the President's rule.

श्री उपसभापति : ठीक है, बोलिए।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : उपसभापति महोदय, आज हम लोगों के सामने यह एक विचित्र स्थिति आई है। सदन को सोचना चाहिए कि यहां दिल्ली के अन्दर अभी-अभी चुनाव हुआ, लेकिन उसकी यह हालत क्यों हुई कि दिल्ली के बजट को संसद में पारित करना पड़ रहा है और यहां पर राष्ट्रपति शासन को सैंक्शन देनी पड़ रही है? उपसभापति महोदय, यह सोचने लायक विषय है।

मैंडेट किसी को नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय लिया, चूंकि दिल्ली की जनता ने दो चीज़ें एक साथ की थीं। पहला तो उन्होंने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका, जिस सत्ता पर 15 साल से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व था और दूसरा दिल्ली की जनता ने किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनादेश मिला, जनमत मिला, लेकिन दिल्ली की जो हालत थी, जो राजनीति थी, उसे देखते हुए हम लोगों ने एक जिम्मेदारी का कदम उठाया और हम लोगों ने तय किया कि हम विपक्ष में बैठेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू हो अथवा दोबारा चुनाव करवाए जाएं, इसमें से हमने दोबारा चुनाव का रास्ता चुना। हमने मौकापरस्ती को राजनीति का रास्ता नहीं अपनाया।

उपसभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने एक समूह से नयी-नयी दोस्ती कर ली, जिसने इनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और इनके एक-एक काम को चुनौती देते हुए निन्दा की। जिस दल को मेंडेट नहीं मिला, ऐसे आधे-अधूरे मेंडेट वाले दल से इन्होंने नरेन्द्र मोदी जी के डर से, भारतीय जनता पार्टी के डर से दोस्ती की, ताकि चार राज्यों में इनका नाम हवा न हो जाए। राजस्थान

[श्री धर्मेंद्र प्रधान]

में इनकी जड़ उखड़ गई, मध्य प्रदेश में इनकी जड़ उखड़ गई, छत्तीसगढ़ में इनकी जड़ उखड़ गई, लेकिन दिल्ली में इनकी जड़ उखड़ने से इनको जो पीड़ा हुई, उसी के कारण इन्होंने इस प्रकार की एक गैर-परम्परावादी राजनीतिक पार्टी को, अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी को सरकार बनाने में मदद की। जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, जिस पार्टी को मेंडेट नहीं मिला था, जिसको लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, उस पार्टी ने सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, इन दोनों ने मिल कर दिल्ली में एक विचित्र स्थिति, एक अनार्की खड़ी कर दी। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभापति महोदय, आज देश में और विशेषकर दिल्ली में संवैधानिक...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दिल्ली में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इस संवैधानिक संकट में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार के इस कदम को समर्थन देते हैं। दिल्ली की इस विपत्ति को देखते हुए, दिल्ली की जनता को एक शासन व्यवस्था देने के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सरकार जो बिल लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस मौकापरस्ती और दिल्ली की जनता के प्रति उन्होंने जो अन्याय किया, उसकी निन्दा करते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Chandan Mitra, do you want to say anything?

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): I will speak on the Delhi Rent (Repeal) Bill. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Minister, do you want to say anything?

श्री आर.पी.एन. सिंह : सर, माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति शासन पर कुछ बातें कही हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): I would like to be enlightened why the Delhi Assembly is not dissolved, just for information sake, so that we have a proper understanding.

श्री आर.पी.एन. सिंह : सर, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने राष्ट्रपति शासन पर कम बातें कही हैं। जो दिल्ली की जनता ने उनको सरकार नहीं बनाने दी है, मैं समझ सकता हूं की इसकी उनको बड़ी पीड़ा है। 2004 में भी उन्होंने इसी तरह कहा था कि हमारी सरकार अवश्य बनेगी, देश चमक रहा है, इंडिया शाइन कर रहा है। उस समय भी उनको झटका लगा था। 2009 में भी उन्होंने इसी तरह भाषण दिए थे और पूरे देश को बताया था कि वे सत्ता में आ रहे हैं और देश को बदलेंगे। 2009 में भी उनको धक्का लगा। अब उनको फिर लग रहा है, जब 2014 के चुनाव आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि उन्होंने इस देश

को जो सपने दिखाए हैं, जो झूठे अपने दिखाने की कोशिश करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वे भी...(**व्यवधान**)... वे भी सरकार...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You reply to the specific question. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, you reply to the specific question. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Mr. Deputy Chairman, you gave him permission to speak two sentences. ...*(Interruptions)*... You allowed him to continue. ...*(Interruptions)*... He must have the right to respond. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Minister is replying. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर,...(**व्यवधान**)... घूम-घूम कर दिल्ली में...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि...(**व्यवधान**)... वे घूम-घूम कर दिल्ली में...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्रधान जी, बैठिए।...(**व्यवधान**)... पुंज जी, बैठिए।...(**व्यवधान**)... आप दोनों बैठिए।...(**व्यवधान**)... Minister will reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI R.P.N. SINGH: I would like to reply to what Mr. Venkaiah Naidu raised, the issue why we have got President's Rule in Delhi. Once the Chief Minister asked for the House for dissolution, it was referred to the Law Ministry. As everybody knows, as Mr. Pradhan also pointed out, only sixty days the Government continued and four years and ten months are still left for the Government. S.R. Bommai *vs.* Union of India case 1994, "When there is a possibility of another Government being formed...", citing that case of 1994, the Law Ministry referred it to us, and we sent it to the Union Cabinet. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He is a very promising Minister. I don't want to disrupt him. ...*(Interruptions)*... S.R. Bommai case verdict is not preventing you from going by the recommendation. ...*(Interruptions)*... I agree that alternative possibility should be explored. The BJP said 'No'; AAP said कि हमसे होगा नहीं। तो बचा कौन? आठ सीटों वाली कांग्रेस। क्या वह सरकार बनाने की स्थिति में है? क्यों हम लोगों को ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि फिर तोड़-फोड़ होगी और कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा मैसेज क्यों दे रहे हैं? क्या इसके बारे में सरकार ने सोचा है?

श्री आर.पी.एन. सिंह : सर, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी सरकार बनाने के लिए 4 साल 10 महीने का टेन्योर बाकी है। अब इसके लिए क्योंकि तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, पूरा हाउस जानता है कि इसके लिए तमाम रास्ते सामने खुले हुए हैं, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया और इसलिए उसको ...(**व्यवधान**)...

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश) : सर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।...(**व्यवधान**)...

[श्री आर.पी.एन. सिंह[

श्री आर.पी.एन. सिंह : मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं।...**(व्यवधान)**... आप लोगों ने खुद ऐसी सरकारें बनायी हैं, पूरे देश में जो सरकारें माइनॉरिटी में रही हैं, कई बार दूसरी सरकारें बनने का मौका आया है। हर आठ दिन में अगर हम चुनाव करवाते रहेंगे, without exploring all the possibilities, तब तो बहुत मुश्किल होगी। That is why we have taken this decision.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Sir, since the hon. Minister has referred to S.R. Bommai case and Article 356 here while bringing a Resolution for bringing President's rule in Delhi, I would like to say that we are thankful to the Supreme Court for its judgment in the S.R. Bommai case. Otherwise, our party has been the victim not once but twice. Under Article 356, our Government became the victim twice. But, due to the S.R. Bommai case, all the regional parties...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: S.R. Bommai case is not the issue here.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY: I know this, Sir. I just want to bring it on record here. The Minister is quoting it in a different way. In the absence of 1994 verdict, all the regional parties may be at the mercy of the Central Government. Otherwise, Article 356 is there and they will use it and they will just do away with our Governments.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, when electoral rolls are ready, Lok Sabha polls are going to happen in the month of April, why does the Union Government want to have a second round of elections?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has given the reply. ...*(Interruptions)*... He has replied to that.

DR. CHANDAN MITRA: No, it has not been replied to. They will impose so much of expenditure and it is only because of the fear that if Delhi elections are held with the national elections, the result will be in favour of...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. I shall now put...*(Interruptions)*... No, that's all. ...*(Interruptions)*... I shall now put the Statutory Resolution to vote. ...*(Interruptions)*... No, it's over. ...*(Interruptions)*...

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha): I will ask only one question, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, one question only.

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, now that the President's rule is being imposed in Delhi, I would like to know from the hon. Minister as to what happens to the famous FIR which Mr. Arvind Kejriwal of Delhi Government had registered against Mr. Moily and so many other people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is not relevant here. That question is disallowed. It is not relevant here. ...*(Interruptions)*... That is not relevant here. The Minister need not reply to that.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Today, Arvind Kejriwal is holding a Press conference about KG-Basin scam...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay...*(Interruptions)*... I cannot allow this. ...*(Interruptions)*... I shall now put the Statutory Resolution...*(Interruptions)*... No. Mr. Gehlot, please sit down. ...*(Interruptions)*... No, you can't ask like that. I am not allowing anybody now.

I shall now put the Statutory Resolution to vote. The question is:

> "That this House approves the Order under Article 239AB of the Constitution issued by the President on the 16th February, 2014 read with Section 50 of the GNCTD Act, 1991 and clauses (2) and (3) of Article 356 of the Constitution in relation to the Government of National Capital Territory of Delhi."

The motion was adopted.

THE INTERIM BUDGET (GENERAL) 2014-15

AND

GOVERNMENT BILLS

(i) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014
(ii) The Appropriation Bill, 2014
and
(iii) The Finance Bill, 2014

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Interim Budget (General) 2014-15, and Bills for consideration and return, namely, the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014, the Appropriation Bill, 2014, and the Finance Bill, 2014. All these will be discussed together but we have already decided that you can ask some questions, those who are very particular can ask questions. That is all. No discussion will be there. Now, Shri Namo Narain Meena to move the Bills.

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, I just have one question before he moves the Bills.